भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1335

03 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय : काजू उद्योग का संकट

1335. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रनः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने काजू उद्योग के संकट के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार काजू उद्योग के पुनरूद्धार के लिए कोई योजना शुरू करने हेतु कार्रवाई शुरू करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने केरल में काजू उद्योग को बचाने के लिए कोई योजना शुरू करने के लिए वित्त विभाग के साथ चर्चा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि केरल सरकार द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार योजना को बैंकों द्वारा कार्यान्वित नहीं किया गया है और यदि हां, तो इसे लागू करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(च) क्या सरकार ने केरल में काजू उद्योग के बंद होने के कारण बेरोजगारी और सामाजिक प्रभाव के संबंध में अध्ययन कराया है; और

(छ) यदि हां, तो इस संकट के समाधान के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क) और (ख): जी हां, उद्योग और वाणिज्य निदेशालय, केरल सरकार ने केरल में काजू उद्योग के विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों को सुलझाने के लिए पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। वाणिज्य मंत्रालय के तहत, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने मैसर्स क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड (क्रिसिल) को "काजू सहित चयनित मूल्यवर्धित कृषि उत्पादों के लिए बाजार के आकलन और उनके निर्यात को बढ़ाने के लिए हस्तक्षेप" पर एक अध्ययन दिया है।

(ग): जी हां, उद्योग एवं वाणिज्य निदेशालय, केरल सरकार ने काजू क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए काजू क्षेत्र के पुनरुद्धार, कायाकल्प एवं पुनरुत्थान नामक एक योजना शुरू की है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत काजू एवं कोको विकास निदेशालय (डीसीसीडी), कोच्चि, केरल भी एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के अंतर्गत, किसानों को सहायता प्रदान करने के माध्यम से क्षेत्र विस्तार, उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य सहित काजू की खेती के विकास को बढ़ावा दे रहा है, जैसे क्षेत्र विस्तार, सेनाइल बागानों का कायाकल्प तथा उत्पादन में सुधार के लिए किसानों के लिए क्षमता वर्धन। किसानों को दी जाने वाली सहायता का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(घ) और (ङ): जी हां, उद्योग और वाणिज्य निदेशालय, केरल सरकार ने अपने वित्त विभाग की सहमति से, काजू क्षेत्र के लिए योजना की शुरूआत की है और छोटे तथा मध्यम काजू कारखाना यूनिट्स को पूंजी अनुदान और ब्याज सहायता के लिए सहायता प्रदान की जाती है। उनके अधिकारियों ने सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए बैंकों को सूचित किया है। इसके अलावा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एपीडा, देश में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन योजना के तहत निर्यात इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, गुणवत्ता विकास और बाजार विकास के लिए केरल राज्य सहित निर्यात संवर्धन के लिए सहायता प्रदान कर रहा है।

(च) और (छ): उद्योग एवं वाणिज्य निदेशालय, केरल सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने केरल में काजू उद्योग के बंद होने के कारण बेरोजगारी और सामाजिक प्रभाव के बारे में अध्ययन किया है तथा नियोक्ताओं के वित्तीय संकट के निपटान हेतु वन टाइम सेटल्मन्ट (ओटीएस) योजना शुरू की है।

अनुलग्नक

एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के अंतर्गत काजू एवं कोको विकास निदेशालय (डीसीसीडी) की काजू विकास योजनाएं

क्रम सं.	योजना घटक	सहायता का पैटर्न
1.	ड्रिप के बिना काजू के नए बागवानों (हेक्टेयर) की स्थापना	तीन किस्तों में 60:20:20 के अनुपात में रोपण सामग्री की लागत और आईएनएम/आईपीएम की लागत को पूरा करने के लिए 20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर (लागत का 40%) (तीन वर्षीय कार्यक्रम)
2.	पुराने वृक्षारोपणों के स्थान पर उच्च उपज देने वाली किस्मों को लगाकर नए वृक्षारोपण	60:20:20 के अनुपात में तीन किस्तों में रोपण सामग्री की लागत और आईएनएम/आईपीएम की लागत को पूरा करने के लिए 20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर,
3.	ड्रिप सिंचाई के साथ उच्च घनत्व रोपण के साथ प्रदर्शन भूखंडों की स्थापना	इनपुट की लागत को पूरा करने के लिए 1 हेक्टेयर की यूनिट के लिए अधिकतम 1.125 लाख रुपये (कुल लागत का 75%)।
4.	काजू में उच्च घनत्व वाले प्रदर्शन भूखंडों की स्थापना	इनपुट की लागत को पूरा करने के लिए 1 हेक्टेयर की प्रति यूनिट अधिकतम 0.40 लाख रुपये
5.	ड्रिप सिंचाई के साथ सामान्य घनत्व में उच्च उपज वाली किस्म के प्रदर्शन भूखंडों की स्थापना	इनपुट की लागत को पूरा करने के लिए 1 हेक्टेयर की प्रति यूनिट अधिकतम 0.75 लाख रुपये
6.	सामान्य घनत्व के साथ विविध प्रदर्शन	इनपुट की लागत को पूरा करने के लिए 1 हेक्टेयर की यूनिट के लिए अधिकतम 0.20 लाख रुपये।
7.	छोटी काजू नर्सरियों की स्थापना	छोटी नर्सरी के लिए अधिकतम 7.50 लाख रुपये क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड सब्सिडी के रूप में। सार्वजनिक संस्थानों के लिए बैंक प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है।
8.	नर्सरियों का उन्नयन/आधुनिकीकरण	आधुनिकीकरण/उन्नयन: वितीय सहायता अधिकतम 5.00 लाख रुपये/नर्सरी तक।
9.	जिला स्तरीय संगोष्ठी	अधिकतम 75,000/- रुपये प्रति दिन के इवेंट के अधीन 100% सहायता
10.	काजू मेला/दिवस	प्रति इवेंट अधिकतम 0.50-3.00 लाख रुपये
11.	काजू उपयोग प्रशिक्षण	25 प्रतिभागियों के प्रति बैच के लिए 1 दिन के प्रशिक्षण हेतु 20,000/- रुपए
12.	काजू उत्पादन तकनीक पर किसानों को प्रशिक्षण	50 प्रतिभागियों के प्रति बैच के लिए एक दिन के प्रशिक्षण हेतु 30,000/- रुपये
13.	एक्सपोजर विजिट	50 किसानों के प्रति समूह के लिए 7 दिन के दौरे के लिए 2.75 लाख रुपये
14.	काजू में प्राइमेरी प्रोसेसिंग यूनिट	ऋण लिंक्ड बैक-एंडेड सब्सिडी पूंजीगत लागत का 40% (अधिकतम 10.00 लाख रुपये)।

*****